छह नए औद्योगिक क्षेत्रों से निवेश उतरेगा धरातल पर

पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग काम्प्लेक्स बनाने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में निवेशकों से किए गए वादे पर खरा उतरने के लिए योगी सरकार ने आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास के ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए खजाना खोला है। प्रमुख एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति देने के लिए बजट में प्रविधान किया है तो पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे छह इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग काम्प्लेक्स बनाने की बड़ी घोषणा की है। इन दोनों क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सरकार पांच-पांच हजार करोड़ रुपये व्यय करेगी। इनमें चार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे तथा दो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे।

प्रदेश सरकार के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये का बजटीय प्रविधान है। गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

ओडीओपी के लिए यूनिटी माल की होगी स्थापना : ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी माल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रविधान है। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

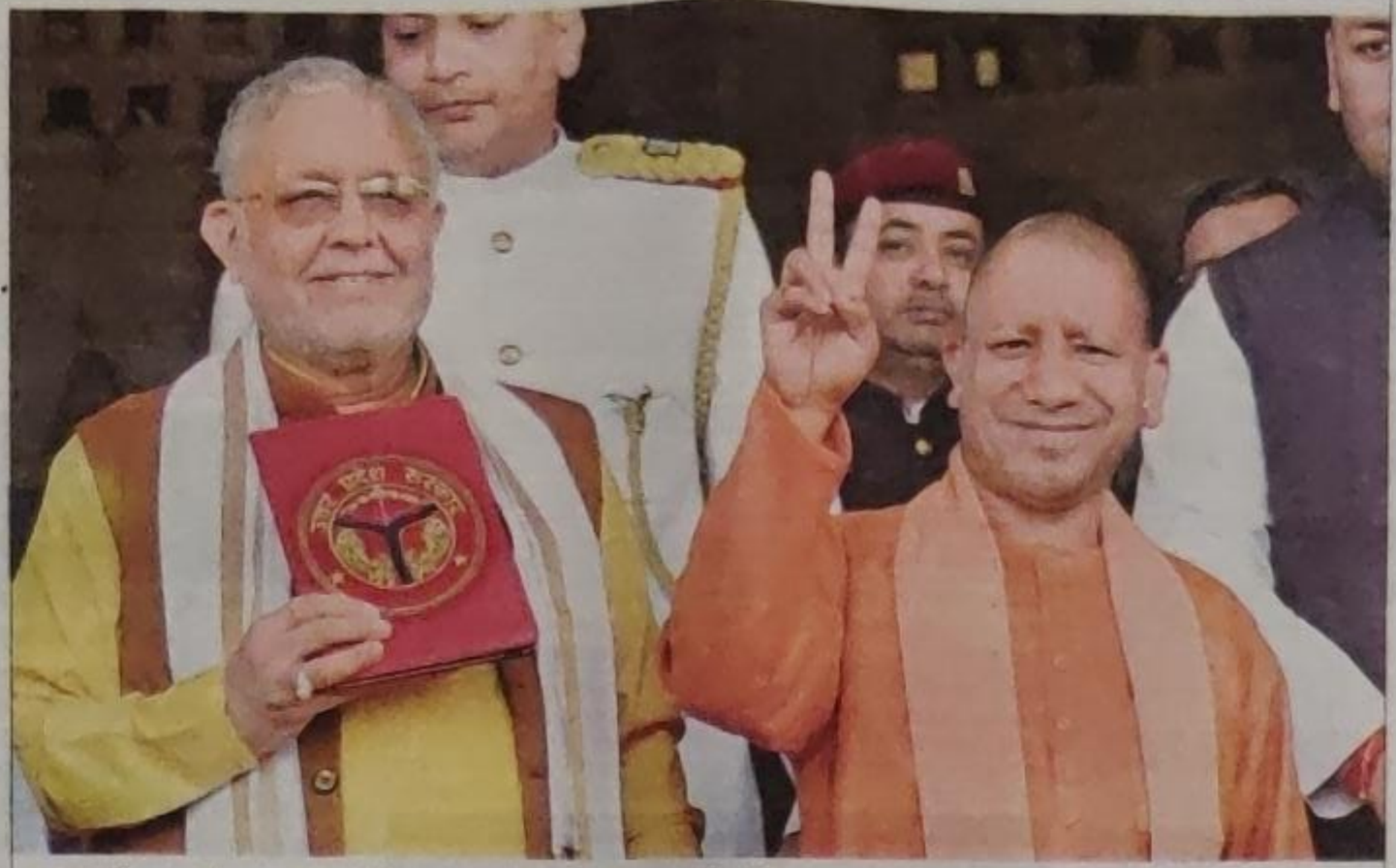

बुधवार को विधान भवन में बजट प्रस्तुत करने के लिए जाते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • रंजनाथ तिवारी

आधारभूत संरचना

235 करोड़ रुपये झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के नए प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित

550 करोड़ रुपये का प्रविधान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारिडोर के लिए किया गया

200 करोड़ रुपये गोरखपुर में इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए प्रस्तावित

200 करोड़ रुपये से ओडीओपी के लिए यूनिटी माल बनाया जाएगा

शहरों की सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये

सरकार ने शहरों की सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इसके तहत चित्रकूट, विंध्याचल, नैमिषारण्य, कुशीनगर, श्रावस्ती, देवीपाटन आदि में पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, सड़क, मार्ग प्रकाश व सौंदर्यीकरण आदि का काम कराया जाएगा।

नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए तीन हजार करोड़

आवास विभाग को योगी सरकार ने 6978.58 करोड़ रुपये का बजट दिया है। पिछले वर्ष 3609.90 करोड़ रुपये ही दिए गए थे। इस बार सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना में तीन हजार करोड़ रुपये की बड़ी रकम दी है। इससे हाल ही में गांव से शहरों में शामिल होने वाले नगरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

- अमृत-2.0 में पेयजल और सीवरेज के लिए 5616 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 2707.86 करोड़ रुपये
- आकांक्षी नगर निकाय योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
- सभी विकास प्राधिकरणों व नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं रोपवे के लिए 100 करोड़

₹10,203 करोड़ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए

शुरू होगी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना : योगी

- अयोध्या बनेगी माडल सोलर सिटी बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कारिडोर
- सौ पिछड़े निकायों में सुविधाओं के विकास को आकांक्षी नगर योजना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सुरक्षा बीमा योजना संचालित करेगी। किसी आपदा या दुर्घटना में उद्यमी या कामगार की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पांच लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। इस योजना की घोषणा बजट में की गई है।

बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री विधान भवन के तिलक हाल में मीडिया से मुखातिब योगी ने कहा कि यह बजट उप्र के त्वरित, सर्व समावेशी और समग्र विकास के साथ उसे आत्मनिर्भर बनाने की नींव डालने का काम करेगा। यह बजट उप्र को अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की आधारशिला रखेगा। योगी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में हमने पारदर्शी तरीके से बढ़ाने का जो प्रयास किया, उसी के फलस्वरूप पिछले छह वर्षों में बजट का आकार दोगुने से ज्यादा हुआ है। वर्ष 2016-17 में बजट का आकार 3.4 लाख करोड़ रुपये था। योगी ने कहा कि हम आकांक्षी नगर योजना के माध्यम से 100 पिछड़े नगर निकायों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करेंगे। हर नगर निकाय में एक-एक सीएम फेलो भी तैनात करेंगे। सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के माडल के तौर पर विकसित करेगी। प्रदेश के अन्य नगर निगमों को भी सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र और जर्मनी के सहयोग से बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कारिडोर विकसित किया जाएगा। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला बनाई जाएगी।

> बजट में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की हिस्सेदारी जो 2016-17 में 33 प्रतिशत थी, अब बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई है। पहले हम पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान पर बजट का आठ प्रतिशत खर्च करते थे, अब छह प्रतिशत कर रहे हैं। 2016-17 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17 प्रतिशत थी जो घटकर चार प्रतिशत रह गई है। प्रदेश में बैंकों का ऋण जमा अनुपात भी 46 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।
>
> योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

अपने गांव में स्कूल-कालेज अस्पताल बना सकेंगे प्रवासी

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में उप्र मातृभूमि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रदेश से जुड़े प्रवासी भारतीय अपने पैतृक गांव में अपने पूर्वजों के नाम से स्कूल, कालेज, अस्पताल, धार्मिक स्थल जैसी संपत्ति/सुविधाएं विकसित कर सकते हैं। राज्य सरकार उन्हें इसके लिए स्थान उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अनुबंध होगा।

विधायक निधि पांच करोड़ रुपये करने का भी इंतजाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक निधि की राशि को तीन करोड़ रुपये से बढ़कर पांच करोड़ रुपये करने के लिए भी बजट प्रविधान कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष विधायक निधि की राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी।